रामकिशन और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य

2 सितंबर, 1997

[डॉ. ए. एस. आनंद और के. वेंकटस्वामी, न्यायाधिपतिगण]

भारतीय दंड संहिता, 1860:

धाराये 304 (भाग-II)/149 और 148-पांच अपीलार्थियों सहित दस आरोपियों पर धारा 302/148 के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया - अभियोजन मामला यह दर्शाता है कि 10-12 व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया था, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई और अन्य को चोटें आईं। उच्च न्यायालय ने पांच आरोपियों को बरी कर दिया और पांच अपीलकर्ताओं को धारा 302 और धारा 148 के तहत दोषी ठहराया - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए - अभिनिर्धारित किया, विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के आधार पर, अपीलकर्ताओं का इरादा केवल मृतक को चोट पहुंचाने का हो सकता था और उन्होंने मृतक की मृत्यु का कारण बनने का कोई सामान्य इरादा साझा नहीं किया था - चिकित्सीय साक्ष्य भी विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए अंतिम निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते हैं - इन परिस्थितियों में मामला 304, भाग

II सपठित धारा 149 के अंतर्गत आएगा - धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि और सजा को रदद किया जाता है - अपीलकर्ता अंतर्गत धारा 304 भाग।। सपठित 149 में दोषी ठहराये गये -उनमें से प्रत्येक को 5 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा।

धारा 149 - हालांकि धारा 149 की प्रयोज्यता को दर्शाने वाला कोई विशेष परिवर्तन फ्रेम नहीं किया गया था, लेकिन धारा के सभी अवयवों को अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था - अभियोग में धारा 149 का उल्लेख न करना एक अनियमितता मात्र है।

विली (विलियम) स्लेनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर (1956) एससी 116, अनुसरण किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 626/1986

राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी.सी.आर.एल. क्रमांक 554/1983 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 6.5.86 से

शांति स्वरूप शर्मा, (एनपी), अपीलकर्ताओं के लिए

के.एस. भाटी, प्रतिवादीगण की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था:

पांच अपीलकर्ताओं के साथ पांच अन्य पर आईपीसी की धारा 302, 148 और कुछ छोटे अपराधों के तहत मुकदमा चलाया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं के पांच सह-आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन उन्हें आईपीसी की धारा 302/148 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई। उन्होंने उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की जिसे 6 मई, 1986 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। विशेष अनुमति द्वारा अपीलकर्ताओं ने 6 मई, 1986 के उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाया है।

संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 14 नवंबर, 1981 को लगभग रात 10 बजे जब परिवादी पक्ष अपनी बैलगाड़ी को आबादी के रास्ते से होते हुए गांव गलिया कुआ की ओर ले जा रहा था, तो गाड़ी को अचानक जोरदार झटका लगा। यह देखा गया कि रास्ते में एक खाई ताजा खोदी गई थी, हालांकि शिकायतकर्ता पक्ष को शाम को जंगलों की ओर जाते समय पहले ऐसी किसी खाई के अस्तित्व पर ध्यान नहीं आया था। बैलगाड़ी को झटका लगते ही रंजीता और हीरा के घर से 10-12 लोग बाहर निकल आए। वे लाठियों और कुल्हाड़ियों से लैस थे। उन्होंने भूरा, बद्री, धन्ना और रामफूल के साथ मारपीट की। हालांकि, रामफूल और धन्ना बाल-बाल बच गए। भूरा ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। बद्री को भी चोटें आईं। रामफूल, पीडब्लू. 3, पुलिस स्टेशन गए और 15 नवंबर 1981

को सुबह लगभग 6.45 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच हाथ में ली गई और पांच अपीलकर्ताओं सहित दस व्यक्तियों को अन्वीक्षा के लिए भेजा गया। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार हमलावरों ने 1973 में हुई एक हिंसक घटना का बदला लेने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया था और भूरा और बद्री को चोटें पहुंचाई थीं, जब अपीलकर्ता रंजीता के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जो कि भूरा और रामफूल के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दायर करने में परिणित हुआ। मुकदमे में अभियोजन पक्ष द्वारा कम से कम 11 गवाहों को परीक्षित कराया गया। 15 नवंबर 1981 को दोपहर 2.30 बजे डॉ. बंसल, पीडब्लू ने भूरा के शव का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने शव पर 11 चोटें देखीं। इन चोटों में से आठ कटे हुए घाव थे और अन्य कुंद हथियार से लगी चोटें थीं। कटे घावों में से कुछ चोटें पैर और बाएं अंगूठे पर थीं और बाकी तीन चोटें मृतक के सिर पर थीं। बद्री, पीडब्लू की भी जांच की गई और उसके शरीर पर नौ चोटें पाई गईं। किसी भी हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, हालांकि उनकी कुछ चोटों को गंभीर चोटें बताया गया। मुकदमे में, डॉ. बंसल ने कहा कि मृतक पर पाई गई चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। हालाँकि जिरह के दौरान डॉ. बंसल ने स्वीकार किया कि इसके अलावा, धारदार हथियारों से लगी चोटों के अलावा मृतक के शरीर पर अन्य चोटें भी थीं और "अन्य चोटों के कारण भी उसकी मृत्यु हो सकती थी"। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 22 नवंबर,

1981 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर कुछ हथियारों की बरामदगी पर भी भरोसा किया।

विचारण न्यायालय ने पाया कि मामले में आरोपियों के दो समूह थे, एक कुम्हार जाति से था जबकि दूसरा गूजर समुदाय से था। अपीलकर्ता गुजर समुदाय से हैं। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि जिन चश्मदीद गवाहों ने न केवल अपीलकर्ताओं बल्कि कुम्हार जाति के पांच अन्य लोगों को भी फंसाया था, उनके सबूतों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सका और परिणामस्वरूप कुम्हार जाति के पांच आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया और उन्हें बरी कर दिया गया।

अपीलकर्ताओं के मामले में, सबूतों की सराहना करने के बाद विचारण न्यायालय ने राय दी कि अपीलकर्ताओं की ओर से किसी भी पूर्व-ध्यान को दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था। यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि 10 आरोपियों में से किसने भूरा को घातक वार किया, जिसके परिणामस्वरूप भूरा की मृत्यु हो गई। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आगे कहा कि "यह एक रहस्य बना हुआ है कि भूरा के हत्यारे कौन हैं"। यह अवलोकन इस संदर्भ में किया गया था कि किसने घातक चोटें पहुंचाई थीं, खासकर तब जब अभियोजन पक्ष के अनुसार कोई भी अपीलकर्ता लाठी से लैस नहीं था और

मृतक को कुछ कुंद हथियार की चोटें लगी थीं। हमने पाया कि अभियोजन पक्ष ने अपराध में अपीलकर्ताओं की मिलीभगत को स्थापित किया है, लेकिन सवाल, हालांकि, उनके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति के बारे में है।

वास्तविक चुनौती से निपटते हुए, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने कहा:

"चूंकि भूरा और रामफूल ने रंजीता का पैर तोड़ दिया था और वे वहां से लकड़ी लाने के लिए बैलगाड़ी पर 'फुटा डूंगर' जा रहे थे, उस स्थिति में गूजर आरोपियों ने गाड़ी में बाधा डालकर उन पर हमला करने और उन्हें घायल करने का इरादा किया होगा।"

(जोर दिया गया)

विचारण न्यायालय ने निरीक्षण किया:

"चूंकि इस तथ्य के संबंध में पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं हैं कि सभी पांच आरोपी मृतक भूरा की मौत का कारण बनने में शामिल थे और पांचों आरोपी एक ही 'पोल' से निकले थे, इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने घटना से पहले मृतक भूरा को मारने के लिए गैरकानूनी सभा का गठन किया था। लेकिन 'मारपीट' शुरू होने के बाद उन्होंने (आरोपियों ने) गंभीर चोटे पहुंचाई (मृतक) भूरा को चोट पहुँचाई।"

जहां तक वसूली का सवाल है, विचारण न्यायालय ने इस पर सही विश्वास नहीं किया और कहा:

"इसलिए, मुझे यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि सभी दस आरोपियों को 15.11.81 को गिरफ्तार किया गया था और 21.11.1981 को उनकी गिरफ्तारी और 22.11.1981 को प्रकटीकरण बयान और हथियारों की बरामदगी के संबंध में सभी सबूत मनगढ़ंत और झूठे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसंधान अधिकारी ने अभियोजन मामले को मजबूत करने के उत्साह में इस तरह से कार्य किया है।"

हालाँकि, उपरोक्त सभी निष्कर्षों को दर्ज करने के बावजूद, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को धारा 302 आईपीसी और धारा 148 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय ने भी उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। हमारी राय में अपराध की प्रकृति के प्रश्न पर नीचे की दोनों अदालतों का दृष्टिकोण दोषपूर्ण और गलत था।

विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के आधार पर, जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं का इरादा केवल मृतक की बैलगाड़ी में बाधा डालकर उसे चोट पहुँचाना हो सकता है और उन्होने मृतक की मृत्यु कारित करने के लिये कोई सामान्य इरादा भी

साझा नहीं किया था। वास्तव में कुल्हाड़ी से चोट पहुँचाने से यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं को यह एहसास होना चाहिए था कि चोटों से उसकी मृत्यु होने की संभावना थी, लेकिन इससे अपीलकर्ताओं का मामला केवल आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत आएगा, न कि धारा 302 आईपीसी के तहत।

विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के मद्देनजर, हम यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं कि अपीलकर्ताओं का इरादा मृतक भूरा की मृत्यु का कारण था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह निष्कर्ष विचारण न्यायालय की टिप्पणी को उजागर करता है। चिकित्सीय साक्ष्य भी विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए अंतिम निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते हैं। अपीलकर्ताओं के मामले में मामले के स्थापित तथ्यों और परिस्थितियों में अपराध केवल धारा 304 भाग II आईपीसी सपठित धारा 149 आईपीसी के अंतर्गत आयेगा, न कि धारा 302 आईपीसी के तहत। वास्तव में धारा 149 भा.दं.सं. की प्रयोज्यता को दर्शाने वाला कोई विशिष्ट आरोप तय नहीं किया गया था। लेकिन धारा 149 आईपीसी की सभी सामग्री अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप में स्पष्ट रूप से इंगित की गई थी और जैसा कि विली (विलियम) स्लेनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर (1956) एससी 116 में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा

आयोजित किया गया था, आरोप में विशेष रूप से धारा 149 आईपीसी का उल्लेख करने की चूक केवल एक अनियमितता है और चूंकि उस चूक से अपीलकर्ताओं पर कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं हुआ है, यह उनकी सजा को प्रभावित नहीं कर सकता है।

हमारी राय में यह अपील इस हद तक सफल होने योग्य है कि अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए, हम आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हैं और इसके बजाय उन्हें धारा 302 भाग II आईपीसी सपठित धारा 149 आईपीसी के अपराध के लिए दोषी ठहराते हैं और उनमें से प्रत्येक को 5 साल के कठोर कारावास की सजा देते हैं। हालाँकि, आईपीसी की धारा 148 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी गई है। अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं। उन्हें सज़ा का शेष भाग, यदि कोई हो, भुगतने के लिए हिरासत में ले लिया जाएगा।

आर.पी.

अपील स्वीकार गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।